



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2018/आषाढ़ 13, 1940

No. 255]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2018/ASHADHA 13, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 13 जून, 2018

संख्या. टीएएमपी/20/2010-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा दीनदयाल पत्तनन्यास (डीपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप (डीपीटी) भूमि की वर्तमान दर संरचना की वैधता का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/20/2010-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2018 के 8वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (केपीटी) की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना को वैधता के विस्तार के लिए डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2. कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के गांधीधाम टाउनशिप भूमि के पट्टा किराये इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 9 अप्रैल, 2012 के आदेश द्वारा संशोधित किये गए थे और संशोधित पट्टा किरायों को 1 जनवरी 2009 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था और वैधता 5 वर्ष के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2013 निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात् इस प्राधिकरण द्वारा डीपीटी के अनुरोध पर डीपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की वैधता का समय-समय पर विस्तार किया जाता रहा है।
3. डीपीटी की गांधीधाम टाउनशिप भूमि को मौजूदा दर संरचना को वैधता का पिछला विस्तार डीपीटी के अनुरोध पर 14 नवम्बर, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/20/2010-केपीटी के द्वारा 31 मार्च 2018 तक अथवा केपीटी द्वारा दायर किए प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित किराये की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया गया था।
4. डीपीटी ने 11 अप्रैल, 2016 के ई-मेल द्वारा गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना के संशोधन का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव को हितधारकों के साथ परामर्शी प्रक्रिया में लिया गया था। मामले में 30 जुलाई 2016 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन हुआ। डीपीटी ने हमारे 2 अगस्त, 2016 के द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण अपने 2 दिसंबर, 2016 के पत्र के द्वारा प्रस्तुत किया है।
- 5.1. संशोधित भूमि नीति और दिशानिर्देश (एलपीजी) 2014 का पैरा 5.7 बताया है कि यह नीति डीपीटी, मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) टाउनशिपों से संबंधित भूमि को छोड़कर, जिनके लिए अलग से नीति बनायी जाएगी, सभी महापत्तनों के लिए लागू है। अतः हमारे 10 अप्रैल 2014 और 9 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या टीएएमपी/8/2014-सामान्य के द्वारा एमओएस को यह अनुरोध किया गया था कि यह स्पष्ट किया जाए कि जब तक अलग से नीति नहीं बनती तब तक कांडला के टाउनशिप क्षेत्र की दरों का संशोधन किस एलपीजी के अंतर्गत शामिल किया जाए। इसके उपरांत 22 अप्रैल, 2016, 28 जून, 2016 और 14 जुलाई, 2016 को भी अनुवर्ती पत्र संख्या टीएएमपी/25/2016-केपीटी भेजे गए थे।
- 5.2. इस संबंध में, एमओएस ने अपने 2 अगस्त, 2016 के पत्र संख्या 8(19)/2016 टीएएमपी के द्वारा सूचित किया है कि गांधीधाम टाउनशिप से संबंधित भूमि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव एमओएस द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए, एमओएस ने डीपीटी के गांधीधाम टाउनशिप की दर संरचना के संशोधन के डीपीटी के प्रस्ताव को रोके रखने और इस संबंध में एमओएस द्वारा नीति की संसूचना के पश्चात् आरंभ करने का अनुरोध किया।
- 5.3. चूंकि मामला अप्रैल, 2016 से निपटान के लिए लंबित है और यह मानते हुए कि मामले को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रखा जा सकता, इस प्राधिकरण ने 21 जुलाई, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/25/2016-केपीटी के द्वारा डीपीटी के 11 अप्रैल, 2016 के विस्तार को बंद करने का निर्णय लिया। इस प्राधिकरण ने यह निर्णय दिया कि एमओएस द्वारा संसूचित नई नीति के आधार पर डीपीटी से जब कभी संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होगा उसे नया मामला समझा जायेगा।
- 6.1. चूंकि गांधीधाम टाउनशिप की वर्तमान दरों की वैधता 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो गई है, डीपीटी ने अपने 06 अप्रैल, 2018 के द्वारा इस प्राधिकरण के 6 महीने की और अवधि के लिए यानी 30 सितम्बर, 2018 तक वर्तमान दरों को प्रभारित करना जारी रखने का अनुरोध इस शर्त पर किया कि संशोधित दरें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी।
- 6.2. उक्त को देखते हुए और चूंकि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो गई है, यह प्राधिकरण गांधीधाम टाउनशिप भूमि की वर्तमान दर संरचना की 30 सितम्बर, 2018 तक अथवा डीपीटी द्वारा दायर प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना की तारीख तक जो भी पहले हो, डीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित विस्तार करता है।
- 7.1. सरकार द्वारा जारी भूमि नीति दिशानिर्देश 2010 (जिसके आधार पर गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना अप्रैल, 2012 में नियत की गई थी) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तब तक होती रहेगी जब तक उनका संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 2012 में अनुमोदिन आदेश में भी इस संबंध में विशिष्ट शर्त निर्धारित की गयी थी। यह शर्त पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी

संशोधित भूमि दिशानिर्देश, 2014 में अभिभावी है। चूंकि मौजूदा पट्टा किराया अनुसूची में जब पट्टा किरायों में इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं किया जाता तब तक पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इसलिए 2 प्रतिशत की दर पर वार्षिक वृद्धि गांधीधाम टाउनशिप भूमि की दर संरचना की विस्तारित अवधि के दौरान लागू रहेगी।

7.2. फिर भी, इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टा किरायों का विस्तार वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में केपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर गांधीधाम टाउनशिप के लिए निर्धारित पट्टा किराया को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना होगा, जैसाकि केपीटी ने अनुरोध किया है।

8. परिणाम में और सामूहिक विचार-विमर्श के उपरांत ऊपर बताये गए कारणों से यह प्राधिकरण, गांधीधाम टाउनशिप भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता को उसकी समाप्ति की तारीख को 30 सितम्बर, 2018 तक अथवा डीपीटी द्वारा प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा. /128/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th June, 2018

No. TAMP/20/2010-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township land of Deendayal Port Trust (DPT) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/20/2010-KPT

Deendayal Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 8th day of June, 2018)

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land of DPT.

2. The lease rental for the Gandhidham Township Land of DPT was last revised by this Authority vide Order dated 09 April 2012. The lease rental revised by this Authority was given retrospective effect from 01 January 2009 and validity was prescribed for a period of five years, i.e. upto 31 December 2013. Thereafter, this Authority has extended the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of DPT from time to time at the request of DPT.

3. The validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land of DPT was last extended based on the request of DPT vide Order No. TAMP/20/2010-KPT dated 14 November 2017 from the date of expiry till 31 March 2018 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the DPT, whichever is earlier.

4. The DPT, vide its email dated 11 April 2016 submitted its proposal for revision of rate structure for Gandhidham Township Land. The proposal was taken on consultation with the stakeholders. A joint hearing

on the case in reference was held on 30 July 2016. The DPT has vide its letter dated 02 December 2016 submitted additional information/ clarifications sought by us vide our letter dated 02 August 2016.

5.1. Para 5.7 of Amended Land Policy Guidelines (LPG) 2014 states that the Policy is applicable for all Major Ports except for land relating to the Township areas of DPT, Mumbai Port Trust (MBPT) and Kolkata Port Trust (KOPT) for which separate policy will be formulated. Hence, vide our letter No.TAMP/8/2014-Genl. dated 10 April 2014 and 9 February 2016 the MOS was requested to clarify under which LPG the revision of Township area of Kandla will be governed till separate policy is formulated. This was followed up by letters No.TAMP/25/2016-KPT dated 22 April 2016, 28 June 2016 and 14 July 2016.

5.2. In the context, the MOS vide its letter no.8/(19)/2016-TAMP dated 02 August 2016 has informed that a proposal seeking approval of the Union Cabinet on Land relating to Gandhidham Township is being prepared by the MOS. The MOS has, therefore, requested to keep on hold the proposal of DPT for revision of rate structure of Gandhidham Township of DPT and take up after the MOS conveys the policy in this regard. The policy from MOS in this regard is awaited.

5.3. Since the case was pending for disposal since April 2016 and also recognising that the case cannot be kept open indefinitely, this Authority vide Order No.TAMP/25/2016-KPT dated 21 July 2017 closed the proposal dated 11 April 2016 of DPT. This Authority has held that the revised proposal as and when received from DPT based on new policy to be communicated by MOS, will be treated afresh. The Order was notified in the Gazette of India vide Notification no.320 dated 17 August 2017.

6.1. Since the validity of existing rates of Gandhidham Township expired on 31 March 2018, the DPT has, now, vide its letter dated 06 April 2018 requested this Authority to allow it to continue to charge at the existing rates for a further period of 6 months i.e. upto 30 September 2018, subject to condition that revised rates will be made applicable with retrospective effect.

6.2. In view of the above and since the validity of the rate structure for Gandhidham Township Land has expired on 31 March 2018, this Authority extends the validity of the existing rate structure of the Gandhidham township land from the date of its expiry till 30 September 2018 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT.

7.1. The Land Policy Guidelines of 2010 issued by the Government (based on which the rate structure for Gandhidham Township Land has been fixed in April 2012) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order approved by this Authority in April 2012 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the amended Land Policy Guidelines, 2014 issued by the Ministry of Shipping. Since, the existing Schedule of lease rent already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by this Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Gandhidham Township Land.

7.2. However, it is to be noted in this regard that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Gandhidham Township based on the proposal to be filed by the DPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

8. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Gandhidham Township Land from the date of its expiry till 30 September 2018 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty. /128/18]